



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राजशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 जून, 1991/11 ज्येष्ठ, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 9 मई, 1991

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 7/83-II.—क्योंकि श्री प्रेम पाल सिंह, प्रधान- ग्राम पंचायत लाना-भाल्टा, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन ने फौजदारी मामला संख्या 41/2-1988/85/ 57/2-1988 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के अधीन एक वर्ष की कैद बामुशवकत व 500/- जुर्माना तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन एक वर्ष की कैद बामुशवकत व 500/- जुर्माना और ई० सी० एक्ट की धारा 7 के अधीन तीन मास की कैद व 200/- जुर्माना की सजा दिनांक 31-1-1991 को सुनाई है ;

क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9 (5) (बी) के अधीन कोई भी व्यक्ति जो सक्षम न्यायालय से दण्डित हुआ हो, किसी भी पंचायत का पंच, उपप्रधान व प्रधान बना नहीं रह सकता।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) में प्राप्त हैं, जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये, के अन्तर्गत श्री प्रेम पाल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत लाना-भाल्टा, विकास खण्ड पन्छाद, जिला सिरमौर को नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त ढंग से नैतिक पतन के लिए दण्डित होने के कारण पद से निष्कासित किया जाये। इस सन्दर्भ में उनका उत्तर जिलाधीश सिरमौर के माध्यम से कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह (श्री प्रेम पाल सिंह) अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला-171002, 9 मई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 36/88.—क्योंकि श्री प्रकाश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत स्यूल, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी प्रागपुर ने सूचित किया है :—

1. कि उन्होंने निर्माण कार्य सम्बन्धी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, निर्माण कार्य स्यूल बावड़ी, निर्माण कार्य कूहल स्यूल निर्माण कार्य दिदियां कूहल एवं निर्माण कार्य पंचायत घर के निर्माण में विधन डाला है जिन कार्यों के लिए पंचायत को क्रमशः अनुदान की राशि मु0 3000/- मु0 5000/- 19-10-1981 को मु0 8575/- (21-1-84 को) मु0 5000/- (2-6-84 को) एवं मु0 5000/- (16-6-86 को) पंचायत स्यूल को दिए गए थे और इस कारण यह सभी कार्य अधूरे पड़े हैं एवं अपने कृत्य से प्रधान ने अपने कर्तव्य के परिपालन की अनदेखी की है।
2. कि उपरोक्त पांच कार्यों सम्बन्धी अनुदान की कुल राशि मु0 26575/- को न ही प्रधान ने उपयोग किया है और न ही वह निर्माण कार्य पूर्ण किए हैं जिनके लिए वह राशि दी गई थी एवं न ही बार-बार नोटिस देने पर भी यह राशि लौटाई है जो विषय लेखा पैरा बन चुका है।
3. और क्योंकि श्री प्रकाश चन्द उपरोक्त को अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा द्वारा उपरोक्त गतिविधियों के लिए 26-2-88 को पद से निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया और प्रधान ने अपने उत्तर दिनांक में उपरोक्त आरोपों को निराधार बताया है।

और क्योंकि प्रधान के विरुद्ध कथित आरोपों की वास्तविकता जाननी जनहित में आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत तथ्यों को वास्तविकता जानने के लिए जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं और पंचायत अंकेक्षण विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा को प्रस्तुतकर्ता नियुक्त करते हैं और यह आदेश देते हैं कि जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सरकार को उपायुक्त, कांगड़ा की टिप्पणियों सहित इस आदेश के अनुरूप शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

शिमला-2, 13 मई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 10/88.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, नारकण्डा की रिपोर्ट पर श्री दिला राम, प्रधान, ग्राम पंचायत जदौण, विकास खण्ड नारकण्डा, ग्राम पंचायत की धन राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में निम्न आरोपों में संलिप्त पाये जाने पर उपायुक्त, शिमला द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4) 165/85-4798, दिनांक 27 फरवरी, 1989 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया :—

1. यह कि दिनांक 11-11-87 को खण्ड विकास अधिकारी ने अनुदान की राशियों के दुरुपयोग की स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यालय में बुलाया गया परन्तु प्रधान कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ।

2. यह कि मुताबिक बाऊचर संख्या 14, दिनांक 20-4-86 ट्रक अप्रेटर यूनियन, नारकण्डा के ट्रक नं० 4671 द्वारा मु० 750 रुपये रेत का ढुलान लूहरी से नारकण्डा देना दिखाया है। रसीद पर ही यह ब्योरा दिया गया है कि मु० 300 रुपये का रेत पुल निर्माण जिम्मू खड्ड तथा 450 का रेत प्राथमिक पाठशाला भवन जदीण पर प्रयोग हुआ दिखाया है परन्तु नारकण्डा में जिम्मू खड्ड तथा जदीण तक रेत ले जाने का कोई भाड़ा किसी को दिया नहीं दिखाया है, और न ही रेत वसूल करने के किसी व्यक्ति के बाऊचर पर हस्ताक्षर मौजूद हैं। इससे सन्देह होता है कि रेत लहरी से नारकण्डा लाया ही नहीं गया, और बाऊचर बिल्कुल जाली है और प्रधान द्वारा मु० 750 का सरासर दुरुपयोग किया गया है।
3. यह कि बाऊचर संख्या 19, दिनांक शून्य अनुसार मु० 450 ढुलान रेत 80 बोरे कंडयाली से जदीण तक का भाड़ा अदा किया दिखाया है परन्तु कण्डयाली में यह रेत कहाँ से और कब आया, का कोई खर्चा तथा ब्योरा रिकार्ड में नहीं पाया गया। इससे भी सन्देह होता है कि मु० 450 रुपये का खर्चा सन्देह पूर्ण है।
4. विकास खण्ड अधिकारी नारकण्डा की रिपोर्ट दिनांक 1-12-88 अनुसार नवम्बर, 88 के अन्त में प्रधान श्री दिला राम के पास मु० 4200 रुपये रोकड़ बही अनुसार नकद बाकी निकलता है जिसकी पृष्ठ में प्रधान के रोकड़ बही पर हस्ताक्षर मौजूद हैं। नियमानुसार प्रधान अपने पास नकद की राशि नहीं रख सकता जबकि प्रधान ने मई 1987 से नकद बकाया भारी मात्रा में अपने पास रखी है;

और क्योंकि प्रधान श्री दिला राम को जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने उनके कार्यालय समसंख्यक पत्र दिनांक 8-12-88, 27-12-88 तथा 8 जून, 1989 और 4 जनवरी, 1990 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु कारण बातों नोटिस का उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रधान ऊपर वर्णित आरोपों में कुछ नहीं कहना चाहते;

और चूंकि पंचायत निरीक्षक, नारकण्डा द्वारा दिनांक 21 व 22 नवम्बर, 1990 को ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पाई गईं :—

1. पंचायत की रोकड़ बही अनुसार दिनांक 22-11-90 को प्रधान के पास मु० 5160 रुपये नकद बाकी अपने पास अनाधिकृत रूप से रखी है।
2. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान की राशि में से श्री दिला राम प्रधान ने मु० 13724 रुपये नकद बाकी अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी।
3. मु० 500 रुपये रोकड़ बही पृष्ठ 3 पर 27-1-90 को सीमेंट तथा रेत का भाड़ा नारकण्डा से ढकून श्री शेर सिंह को दिया दिखाया जबकि उनके रसीद पर हस्ताक्षर नहीं हैं।
4. मस्ट्रोल मुरम्मत प्राथमिक पाठशाला भवन जदीण दिसम्बर 1989 का मु० 793 का रोकड़ बही के पृष्ठ 2 पर दिनांक 19-1-90 को खर्च दिखाया परन्तु मस्ट्रोल पर दर्ज एक मिस्ती व दो मजदूरों के पावती के हस्ताक्षर नहीं। स्पष्ट है कि मस्ट्रोल की अदायगी ही नहीं की और मु० 793 का श्री दिला राम प्रधान द्वारा गठन किया गया;

और क्योंकि अतिरिक्त उपायुक्त, जिला शिमला द्वारा दिनांक 25-2-91 को पंचायत की धन राशि का गबन/दुरुपयोग करने में प्रधान पद से निलम्बित कर दिया है;

क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत जदीण, विकास खण्ड नारकण्डा को गम्भीर आरोपों में संलिप्तता के कारण उसके विरुद्ध नियमित जांच करावाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (नॉ) रामपुर को कथित आरोपों में वास्तविकता जानने के लिये एवं जनहित में जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, शिमला के माध्यम से अधोहस्तक्षरी को शीघ्र प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्यपाल पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला को रिकार्ड प्रस्तुतकर्ता नियुक्त करते हैं।

शिमला-2, 13 मई, 1991

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)39/80.—क्योंकि श्री बलवन्त सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नेरटी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा को विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-8-90 को ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित होने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अधीन प्रदत्त है, श्री बलवन्त सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नेरटी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा को यह आदेश देते हैं कि वह भविष्य में पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें और यदि किसी कारणवश पंचायत की बैठक में भाग न ले सकें तो यथा समय पूर्व पंचायत को सूचिन करें।

शिमला-2, 15 मई, 1991

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)26/77.—क्योंकि श्री हरनाम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत करगाणु, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर को इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी, 1990 द्वारा पद से निष्कासनार्थ एवं एक वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया :-

1. कि श्री हरनाम सिंह प्रधान उपरोक्त ने धर्मासन का स्वामित्व करते हुए श्रीमती देवकु पत्नी श्री नरपत बनाम केशव राम के मामले में श्रीमती देवकु को विरुद्ध 20 रुपये हरजाना लगाया लेकिन हरजाना लगाते समय कोई लिखित फौसला इस विषय में नहीं दिया, श्री हरनाम सिंह ने 20 रुपये जुर्माना घोषित किया माना है जो पंचायत अभिलेख में वसूल हुआ नहीं पाया है;
2. कि हरनाम सिंह ने जयदत्त पुत्र श्री राम स्वरूप का जन्म प्रमाण-पत्र उसके पिता के हलफिया ब्यान के आधार पर पंचायत सचिव श्री लक्ष्मी सिंह द्वारा यह सूचित करने पर भी कि जन्म सम्बन्धी पंचायत अभिलेख में कोई प्रविष्टि न है जारी करवाया एवं जहां नियमों की अवहेलना की वहां अपने पद का दुरुपयोग किया और उसकी गरिमा को हानि पहुंचाई;
3. कि उपरोक्त प्रधान श्री हरनाम सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुमारी संगीता पुत्री श्री सोम दत्त, ग्राम वटोल जिसका जन्म पंचायत अभिलेख में दर्ज न था का जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया है;
4. कि श्री हरनाम सिंह प्रधान उपरोक्त ग्राम पंचायत करगाणु की बैठकों में मई, 1988 से अगस्त 1988 तक लगातार अनुपस्थित रहे हैं एवं अपनी अनुपस्थिति हेतु सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाये हैं। फलतः उपरोक्त प्रधान ने अपने पद की कर्तव्य परायणता की न केवल उल्लंघना की है बल्कि पंचायत की कार्यकुशलता में भी बाधा डाली है एवं पंचायती राज अधिनियम, 1968 की उप-धारा 2(सी) धारा 54 की उल्लंघना में भी दोषी पाए गए;

और क्योंकि प्रधान का उत्तर एवं उस पर जिलाधीश, सिरमौर की टिप्पणियों का बारीकी से अध्ययन करने पर यह पाया गया कि प्रधान के उपरोक्त ढंग से किए गए कुकृत्यों का कोई औचित्य न है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के उपयोग में जोकि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत प्रदत्त हैं, श्री हरनाम सिंह, प्रधान (निलम्बत), ग्राम पंचायत करगाणु, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर को अपने पद के दुरुपयोग हेतु जहां प्रधान के पद से तुरन्त निष्कासित करने का आदेश देते हैं वहीं उन्हें एक वर्ष के लिए ग्राम पंचायत करगाणु के निर्वाचन हेतु भी अयोग्य घोषित करते हैं एवं यह आदेश भी देते हैं कि वह पंचायत का समस्त रिकार्ड सम्पत्ति रोकड़ आदि जो भी उनके पास हो को पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी) को सौंप दें।

शिमला-2, 15 मई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 19/82.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा, जिला शिमला ने यह सूचित किया है कि ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अंकेक्षण पत्र बाबत अवधि 4/86 से 3/89 के अनुसार प्रधान श्री रणबहादुर सिंह द्वारा निम्नलिखित गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं:—

1. कि उन्होंने दिनांक 6-9-88 को कुल मु0 10,229.73 पैसे एवं दिनांक 30-9-88 को कुल 10,601.77 पैसे बतौर नकद शेष अपने पास रखे जोकि वित्तीय नियमों की सरासर उल्लंघना है और जिस कृत्य से इनके दुरुपयोग और छलहरण की संभावनाओं को नाकारा नहीं जा सकता;
2. प्रधान के नाम पंचायत अभिलेख अनुसार मु0 8500/- रुपये की राशि बतौर पेशगी खड़ी है उनके नाम चली आ रही है जबकि पेशगी लेने का नियमों में कोई प्रावधान न है और इस राशि के छलहरण को नाकारा नहीं जा सकता;
3. कि प्रधान द्वारा पांच व्यक्तियों को पंचायत निधि में से मु0 28245.15 पैसे की पेशगी दी गई जो कि वित्तीय नियमों की सरासर उल्लंघना है और इस राशि के छलहरण को नाकारा नहीं जा सकता;
4. क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत, बसन्तपुर द्वारा इंडियन बैंक मशोबरा के खाते से तथा डाकघर बसन्तपुर के खाता में से ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर क्रमशः क एवं ख पर अंकित विवरण के अनुसार पंचायत निधि से रुपये निकाले गये जिनका विवरण नीचे दिया गया है और इस तरह से प्रधान ने कुल 53895/- रुपये और 16500 रुपये का दुरुपयोग किया है एवं न ही इसका हिसाब पंचायत को दिया गया और न ही यह राशि पंचायत को लौटाई है। प्रधान ने इस कृत्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य, वित्त नियमों 1975 के नियम 4 की उल्लंघना हुई है:—

दिनांक 1	रोकड़ पृष्ठ 2	राशि 3	बैंक/डाकघर 4
-------------	------------------	-----------	-----------------

12-5-1986	62	12000.00	इंडियन बैंक, मशोबरा
15-7-1986	"	1000.00	"
20-8-1986	"	3395.00	"
30-9-1986	63	10000.00	"
2-1-1987	65	11000.00	"
5-2-1987	66	10000.00	"
2-3-1987	"	1500.00	"
6-5-1987	69	5000.00	"

53895.00

1	2	3	4
8-9-1986	69	3000.00	डाक घर बसन्तपुर
9-9-1986	-यथा-	4000.00	-यथा-
11-9-1986	-यथा-	1500.00	-यथा-
5-9-1986	-यथा-	2000.00	-यथा-
23-6-1986	-यथा-	6000.00	-यथा-
		16500.00	

5. और क्योंकि प्रधान उपरोक्त ने नकद शेष में से मु0 1500/- रुपये का इन्द्राज रोकड़ के अनुसार 17-11-1987 को डाकघर, बसन्तपुर में जमा किया दिखाया जबकि पास बुक अनुसार वह राशि वास्तविक रूप में जमा नहीं हुई है। इस प्रकार गलत इन्द्राज दिखा कर उन्होंने जहां इस राशि का दुरुपयोग किया है वहां अपने पद गरिमा को गिराया है।

और क्योंकि इस प्रकार उपरोक्त दिय गये विवरणानुसार श्री रणबहादुर सिंह, प्रधान उपरोक्त ने न केवल पंचायत निधि का दुरुपयोग एवं छलहरण किया है बल्कि अपने अधिकारों का भी दुरुपयोग किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच करवाना जनहित में आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत प्राप्त है जहां जिला पंचायत अधिकारी शिमला को प्रधान के विरुद्ध आरोपों में जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। इस आदेश सहित कि वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त शिमला के माध्यम से सीधे सरकार को प्रस्तुत कर वहां पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड मशौबरा, जिला शिमला को प्रस्तुतकर्ता नियुक्त करते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

शिमला-171002, 15 मई, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 62/88.- क्योंकि श्री कश्मीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत अम्ब, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना को सरकारी भूमि का अनाधिकृत रूप से अधिक्रमण करने के आरोप में सहायक समाहर्ता, अम्ब ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत वेदखल किया गया ;

क्योंकि सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे की दशा में कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9 (5) सी0 सी0 के उपबन्धों के अनुसार किसी ग्राम पंचायत का पंच, उप-प्रधान व प्रधान बना नहीं रह सकता। अतः उपायुक्त, ऊना ने अपने आदेश संख्या पंच-ऊना (4) 54/79-II दिनांक 10-10-89 द्वारा उपर्युक्त प्रधान को पद से निलम्बनार्थ कारण बातों नोटिस पंचायत अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत दिया था ;

क्योंकि श्री कश्मीर सिंह उपरोक्त ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में यह व्यक्त किया है कि विवादग्रस्त भूमि की मालिक ग्राम पंचायत न है और वह उस पर काबिज है जिसके दृष्टिगत उसने सहायक समाहर्ता, तहसील अम्ब के निर्णय के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज ऊना के न्यायालय में अपील कर रखी है ;

क्योंकि इसी विषय में वास्तविकता जानने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-1-90 द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, ऊना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था एवं जांच अधिकारी ने अपन पत्र दिनांक 8-2-90

द्वारा यह सूचित किया है कि जिला जज, ऊना ने अपने आदेश दिनांक 2-2-90 द्वारा सहायक समाहर्ता, अम्ब के आदेश दिनांक 30-6-89 पर स्टै दे रखी है, अतः जांच को याचिका के निर्णय तक स्थगित रखना ठीक है ;

और क्योंकि न्यायालय के स्थगन आदेश के दृष्टिगत विधि विभाग के परामर्श के आधार पर यह पाया गया कि सहायक समाहर्ता का आदेश दिनांक 30-6-89 उन्होंने राजस्व अधिनियम की धारा 163 के अधीन बतौर राजस्व अधिकारी पारित किया है न कि बतौर दिवानी अदालत के। अतः जिला जज द्वारा स्थगन आदेश वैध न हैं क्योंकि ऐसे आदेश देने उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपायुक्त (जिला समाहर्ता), ऊना को जिला जज, ऊना के स्थगन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील/(पूनीरीक्षण) दायर करने के लिए सरकार की ओर से प्राधिकृत करते हैं और यह भी आदेश देते हैं कि इस विषय में वह देरी की मुआफ़ी के लिए भी उचित निवेदन करें और की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करवायें।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 13 मई, 1991

संख्या 1297-1301.—क्योंकि ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा के अंकेक्षण अवधि 4/83 से 3/90 तक की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्री स्वाई राम, प्रधान, ग्राम पंचायत स्थाना ने 900 पत्थर श्री धर्म चन्द सुपुत्र श्री रफलू राम को मु0360 रु0 में बेच कर राशि रसीद संख्या 65/60 दिनांक 17-3-1990 के अन्तर्गत प्राप्त की है परन्तु रोकड़ में केवल तीन रुपये ही दर्ज किये हैं, इसी प्रकार दिनांक 26-3-1990 को 250 स्लेट 10"×20" साइज के श्री वकील सिंह सुपुत्र श्री जगत राम को बेच कर मु0 एक हजार रुपये रसीद संख्या 66/67 के अन्तर्गत प्राप्त किये और रसीद सं0 17/67 के अन्तर्गत श्री राम सिंह सुपुत्र श्री गंगा राम को 50 स्लेट बेच कर मु0 200 रुपये प्राप्त किये हैं परन्तु रोकड़ में इन रसीदों के अन्तर्गत केवल तीन-तीन रुपये ही जमा किये हैं। इस तरह 1560 रुपये में से 1551 रुपये का प्रधान द्वारा गबन किया गया है ;

और क्योंकि जंजघर भानथ की निम्न स्टाक की शेष सामग्री भी उक्त प्रधान के जिम्मे है जो 375.00 रुपये की है :-

वस्तु	मात्रा	मूल्य
सीमेंट	एक बोरी	75.00
स्लेट 10"×20"	एक सौ	300.00

और क्योंकि हरिजन कुआं स्थाना में लत्तैण पर 80 रुपये व्यय दिखाया है जबकि मौके पर बताया गया कि कुएं पर कभी भी लकड़ी की लत्तैण 'नहीं' डाली गई है। मौके पर सीमेंट की लत्तैण पाई गई जिस पर पंचायत न कोई राशि व्यय नहीं की है ;

और क्योंकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मु0 15500/- के अनुदान के स्थान पर केवल 15000 रुपये की आय दिखाई है परन्तु इस अनुदान को जवाहर रोजगार योजना की रोकड़ में हस्तांतरित करते समय 15500 रुपये दिखा कर 500 रुपये की पंचायत क्षति दिखा कर राशि का गबन किया है;

और यह कि नकद शेष की राशि हर समय विहित सीमा से अधिक रख कर पंचायत को क्षति पहुंचा कर राशि का दुरुपयोग करते रहे हैं।

अतः मै. एस0 राय, उपायुक्त, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला उपरोक्त राशियों के छलहरण को ध्यान में रखते हुए श्री स्वाई राम प्रधान, ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अंतर्गत बने पंचायत नियम 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह अपनी स्थिति अधोहस्ताक्षरी को दस दिन के भीतर-भीतर स्पष्ट करें कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से सभा निधि के छलहरण के आरोप में निलम्बित/निष्कासित किया जायें। यदि विहित समय में स्पष्टीकरण नहीं पहुंचा तो यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है और लगाये गये आरोपों को मानते हैं।

एस0 राय,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।